(iii) उन बाल कर्मकारों के लिये विशेष स्कूल स्थापित करना जहां शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य देखरेख आदि की व्यवस्था की जा रही है। जब आवश्यक हो, प्रतिषिद्ध नियोजनों से निकाले गये बालकों को वजीफे दिये जाते है ताकि वे संबंधित परिवारों की आय में हुए नुकसान को पूरा कर सकें।

(iv) सामाजिक कार्यकर्त्ता ग्रुपों और अन्य साधनों द्वारा चेतना का सृजन ताकि बाल श्रमिकों के अवांछनीय पहलुओं के बारे में लोगों को शिक्षित किया जा सके तथा उन्हें विश्वास दिलाया जा सके।

इन परियोजनाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले बाल कर्मकारों की कुल संख्या लगभग 800 है।

(ग) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम के पास सोयाबीन तेल का स्टाक

2787. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भी खाद्य तेलों का आयात किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि तिलहनों के संबंध में गठित प्रौद्योगिकी मिशन ने आयात को निरुत्साहित करके देशीय उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की सलाह दी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि लगभग वर्ष के अंत में स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के भण्डारों में 85,000 टन खाद्य तेल का भण्डार था जिसमें से 50,000 टन सोयाबीन तेल था;

(घ) क्या यह भी सच है कि इतनी बड़ी मात्रा में तेल का भण्डार होने का कारण वनस्पति घी निर्माताओं द्वारा इस तेल का उठाना न था; और

(ङ) यदि हां, तो इस सोयाबीन तेल को खपाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी हां।

(ख) तिलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के कार्य में तेजी लाने के लिए की गई थी। तिलहनों के आयात को निरुत्साहित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सरकार ने न तो कोई आयात किया है और न ही उसे तिलहनों के आयात का कोई प्रस्ताव ही प्राप्त हुआ है।

(ग) वर्ष के अंत पर राज्य व्यापार निगम के पास आयातित खाद्य तेलों की 85,000 मी० टन मात्रा, जिसमें 50,000 मी० टन सोयाबीन का तेल शामिल है, उपलब्ध थी।

(घ) खाद्य तेलों के देशीय उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने दिसम्बर, 1988 में आयातित खाद्य तेलों की 19,000/-रु० प्रति मी० टन की रियायती दर पर आपूर्ति बंद कर दी थी। वनस्पति के लिए आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य बढ़ा देने और देशीय तेलों के कम मूल्यों पर उपलब्ध होने के फलस्वरूप वनस्पति उद्योग द्वारा आयातित तेल नहीं उठाए गए। इस प्रकार राज्य व्यापार निगम के पास खाद्य तेलों के स्टाक का कुछ भाग वनस्पति उद्योग द्वारा तेल न उठाए जाने की वजह से एकत्र हुआ है। इसका अन्य कारण यह है कि इस स्टाक में वह मात्रा शामिल है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए देने हेतु बाद के महीनों में आवंटित किया जाना था।

(ङ) सोयाबीन के तेल के बकाया स्टाक का इस्तेमाल सेना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्यों को आवंटित करने हेतु किया जाएगा।